



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष पर मोतीदुंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की।

## मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश के विकास के लिए पूजा की

डोंग/जयपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 के प्रथम दिन बुधवार को डोंग के श्रीनाथ जी मन्दिर, मुकुट मुखारविंद मन्दिर तथा जयपुर के मोतीदुंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। इस सभ में उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थीं। शर्मा डोंग जिले के श्रीनाथ जी मन्दिर में मंगला आरती में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने मुकुट मुखारविंद मन्दिर में श्री गिरिजा जी का दुग्धाभिषेक किया तथा विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर, भरतपुर रेंज आई जी राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर डोंग उत्सव कोशल, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर

**■ उन्होंने पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मंदिर व मुकुट मुखारविंद मंदिर तथा जयपुर में मोती दुंगरी गणेश जी मंदिर में पूजा-अर्चना की।**

डोंग संतोष कुमार मीणा सहित, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके बाद, मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचे और मोतीदुंगरी गणेश मन्दिर गए, जहाँ उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की। इस अवसर पर गुजरात मंत्री जवाहर सिंह बेदम सहित, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

## अब फ्लाइट में मिलेगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगा। इसी के साथ ही तमाम भारतीय एयरलाइंस में एयर इंडिया पहली एयरलाइंस बन गई है, जिसमें अपनी फ्लाइट में वाई-फाई सर्विस शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने बताया कि शुरूआत में यह सर्विस उसके 300 से अधिक एयरक्राफ्ट के बेड़े में से कुछ ही एयरक्राफ्ट में शुरू की गई है। इनमें सभी छह ए-350, सात बोइंग-787-9 और 10 ए-321 नियों में से चुनिंदा प्लेन में आए। एयर इंडिया के बेड़े में अभी 10 ए-321 नियों एयरक्राफ्ट है।

## जलगांव में दो गुटों में हिंसा

जलगांव, 01 जनवरी। महाराष्ट्र के जलगांव के पारधी में 31 दिसंबर की रात मंत्री गुलाब राव पाटिल के समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ ने 6 गाड़ियों और 15 दुकानों में आग लगा दी। देर रात फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इसके बाद जलगांव में 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पलाढी गांव में 31 दिसंबर की रात पथराव और आगजनी की घटना हुई है। कर्तव्य तौर पर मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को जो लारे वाहन के ड्राइवर द्वारा हॉर्न बजाने से विवाद पैदा हुआ। इसके बाद पलाढी गांव के कुछ युवक और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता चिल्लाने लगे। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पलाढी गांव में पथराव और आगजनी की।

पुलिस ने इस घटना के बारे में कहा है कि बहस मौके पर ही खत्म हो गई थी। हालांकि, लेकिन बाद में इलाके के कुछ लोग गांव के चौराहे पर गए और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एक और समूह वहां पहुंचा, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस ने कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

## केन्द्र ने फसल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कम होगी। सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इससे अधिक किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे किसानों की 50 किलो का डीएपी बैग 1,350 रुपये में मिलता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने यह फैसला किसानों को राहत देने के लिए किया है। सरकार ने किसानों के लिए कुल 69,515 करोड़ रुपये का आउटपुट किया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि का बोझ किसानों पर न पड़े, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।

## इस वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर रहेगा

**■ रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों की बैठक में राजनाथ सिंह ने घोषणा की।**

नई दिल्ली, 01 जनवरी। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित किया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को एक साथ कई क्षेत्रों में संचालन में सक्षम बनाना और उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस लड़ाकू सेना बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, सुधारों और प्रगति की समीक्षा के लिए नव वर्ष की पूर्व संस्था पर मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सिंह ने विषयवस्तु जताया कि यह सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा, यह देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेगा, इस प्रकार 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की तैयारी करेगा। सुधारों का उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण पहल को और मजबूत करना और एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना को सुविधाजनक बनाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए डोमेन और

## कश्मीर में जैश के चार सहयोगी पकड़े

**■ रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों की बैठक में राजनाथ सिंह ने घोषणा की।**

श्रीनगर, 01 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा उप-जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चार आतंकवादी सहयोगियों की पहचान कर ली है। ये हैं जाल पाईन के मुदासिर अहमद नाइक, कुचमुल्ला के उमर नजीर शेख, त्राल पाईन के इनायत फिरोज राथर और कौसरबल जाल निवासी नजीर अहमद लोन। एक पुलिस बयान में कहा गया कि गिरफ्तार किए गए सभी आतंकवादी सहयोगी त्राल और अवंतीपोरा इलाकों में प्रतिबंधित आतंक संगठन जेईएम के सक्रिय आतंकवादियों को रसद सहायता और परिचयों और गोला-बारूद के परिवहन में शामिल थे। इसमें कहा गया है कि उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्रियों का विराम कर दिया गया। जाल पाईन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

## भारत-पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे को सौंपी

**■ वर्ष 2008 के समझौते के अनुसार, हर वर्ष जनवरी व जुलाई में इन सूचियों का आदान-प्रदान होता है।**

प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु स्थापना और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत किया गया है, जिस पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और 27 जनवरी 1991 को यह लागू हुआ था। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान हदली जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 34वां आदान-प्रदान है, पहला आदान-प्रदान एक जनवरी 1992 को हुआ था।

## मुख्यमंत्री करेंगे हजार करोड़ से अधिक के एम.ओ.यू. की मासिक समीक्षा

**सौ से हजार करोड़ के एम.ओ.यू. की समीक्षा मुख्य सचिव तथा सौ से नीचे की विभागीय सचिव करेंगे**

जयपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विज़न एवं रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए एमओयू के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है। एमओयू की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले

- राजिंज राजस्थान में प्रदेश में निवेश के लिये हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारने के लिये राज्य सरकार ने तीन स्तरीय समीक्षा व्यवस्था बनाई है।
- राजिंज राजस्थान के तहत 261 एम.ओ.यू. 1,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि के हैं। सौ से एक हजार करोड़ रूपए के एम.ओ.यू. की संख्या 1,678 है। सौ करोड़ तक के कुल 9,726 एम.ओ.यू. हुए हैं।

एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं, 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी।

साथ ही, 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। राजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35

लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए थे, जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के 261 एमओयू एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले हैं। इसी तरह, 100 करोड़ से अधिक एवं 1 हजार करोड़ रुपये से कम की राशि वाले एमओयू की संख्या 1 हजार 678 तथा इनकी कुल राशि साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के अंकित है।

साथ ही, 100 करोड़ रुपये तक के एमओयू की संख्या 9,726 तथा इनकी कुल राशि लगभग 90 हजार करोड़ रूपए है।

उल्लेखनीय है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षरित हुए एमओयू की प्रगति-रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखने की घोषणा करते हुए, अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी थी। इस दिशा में त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल कारगर साबित होगी।

## जीवित नहीं निकल पाई 3 साल की चेतना बोरवैल से

**समानांतर सुरंग खोदकर 170 फीट नीचे से 10 दिन बाद शव निकाल पाई एन.डी.आर.एफ. टीम**

कोटपतली 01 जनवरी (निस)। कोटपतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी (3) को 170 फीट गहरे गड्ढे से दस दिन बाद बाहर निकाला, हालांकि बच्ची को जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समानांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीणा ने कहा कि बच्ची

**■ एन.डी.आर.एफ. के जवानों ने बताया कि चेतना की बाँड़ी मिट्टी के बीच फंसी थी। अंगुली से उसकी बाँड़ी के आस-पास से मिट्टी हटाई, फिर उसे बाहर निकाल सके।**

**■ चेतना जब गिरी थी तब 25 फीट पर अटकी हुई थी। परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर अपने स्तर पर ही रस्सी डालकर निकालने का प्रयास किया। आशंका है हाथ ऊपर करने से चेतना फिसल कर 80 फीट गहवाई तक चली गई थी।**

को अचेत अवस्था में निकाला गया है, जब उसे निकाला गया, तब उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। बुधवार शाम 6 बजेकर 25 मिनट पर तीन साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेट कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद

चेतना को एंबुलेंस से कोटपतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली की ढागी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें फेल हुई थीं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन को



मृत बालिका चेतना

हटाई। फिर उसे बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। पत्थर उछलकर आंखों पर आ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लोटकर पत्थर तोड़ने पड़े थे। जहां बच्ची फंसी हुई थी, वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था। बच्ची नीचे जाते-जाते वहां फंस गई थी। एक चेतना बोरवेल में गिरी, तब वह महज 15 फीट पर अटकी हुई थी। परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर बोरवेल में रस्सी डालकर अपने लेवल

पर ही उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। आशंका है कि हाथ ऊपर करने से बोरवेल की दीवारों और चेतना के बीच गैप बन गया। इससे वो फिसल कर करीब 80 फीट गहरी तक चली गई।

दोपहर 2 बजे स्थानीय प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई थी। बावजूद इसके, आधे घंटे बाद एसडीआरएफ-एनडीआरएफ को बुलाने का कॉल लिया गया। पौने 3 घंटे बाद, यानी 5.15 बजे के करीब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मासूम फिसलकर करीबन 150 फीट गहरे गड्ढे तक पहुंच गई थी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम 2 घंटे के भीतर पहुंच जाती, तो शायद 80 फीट पर ही चेतना को होल्ड किया जा सकता था।

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन तथा रेस्क्यू टीमों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन में 170 फीट लंबी गहरी खुदाई, विपरित मौसम, ऑपरेशन के दौरान बारिश आदि, सुरंग के अंदर नमी, तापमान अधिक होना, जैसी अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए रेस्क्यू टीम ने आज बच्ची को रेस्क्यू किया।

## आठ पाकिस्तानियों को बीस साल की सजा सुनाई

**इन्हें गुजरात तट पर 232 किलो हेरोइन के साथ 2015 में पकड़ा गया था**

मुंबई, 01 जनवरी। महाराष्ट्र में मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आठ पाकिस्तानी नागरिकों को 2015 में गुजरात तट पर मछली पकड़ने वाली नाव पर 232 किलोग्राम हेरोइन ले जाने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश एस ई बांगर ने आठ आरोपियों को स्वायक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी पाया। दोषियों की पहचान अलीबक्शा खखेली सिंधी, मकसूद अब्दुर यूसुफ मसिम, मोहम्मद बक्शा नाथो, मोहम्मद अहमद मोहम्मद इनायत, मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला गवानी, मोहम्मद युनुस हाजी मोहम्मद सुमार सिंधी, मोहम्मद गुलहसन मौलाबक्शा बलूच सिंधी और गुलहसन मोहम्मद सिद्धी सिंधी के रूप में हुई है। सभी दोषी पाकिस्तानी नागरिक हैं।

**■ मछली पकड़ने वाली नाव के साथ पकड़े गये पाकिस्तानी नागरिक 10 साल जेल में बिता चुके हैं। उन्हें 10 साल और सजा भुगतनी होगी।**

इन सभी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय ये ये लोग जेल में बंद हैं, इसलिए उस अवधि को ध्यान में रखा जाएगा और अब उन्हें जेल में और दस साल बिताने होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में आरोपियों ने मछुआरे होने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी नावों में हेरोइन के पैकेट कितने थे। वहीं, इन लोगों के पास तीन सैटेलाइट फोन थे, जिनका इस्तेमाल

भारत या पाकिस्तान के नागरिकों को के भी अनुमति नहीं है और नाव पर जीपीएस डिवाइस चलाए जा रहे थे, जिससे पता चलता है कि वे भारत जा रहे थे। अदालत ने इस आधार पर मामलों में बरी करने की बचाव पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया कि मुंबई पुलिस के पास इस मामले को संभालने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जन्म अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जिस क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई, वह समुद्री अर्थशास्त्र के अंतर्गत है, इसलिए अदालत ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है।

## बजट 2025-26 में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कम करने के लिए फेसलेस एसेसमेंट सिस्टम लाना शामिल है, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। इन परिवर्तनों से व्यवसायों में भरोसा बढ़ेगा।

भारत में एफ.डी.आई. का प्रवाह हालिया वर्षों में लगातार बढ़ा है और आगामी बजट में ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि प्रवाह की ये गति कायम रहे। इससे मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। निर्माण इकाइयों लगाई जाएंगी और यातायात का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा। इसके अलावा, सरकार अक्षय ऊर्जा, ई-वाहन व अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे सकती है। भारत के तेजी से बढ़ते खुदरा बाजार और ई-कॉमर्स सेक्टर में एफ.डी.आई. के नियमों में छूट दी जा सकती है, ताकि अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें।

टैक्सनीली और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के एफ.डी.आई. के प्रमुख

क्षेत्र बने रहने की संभावना है। सरकार अतिरिक्त कर लाभा व स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का प्रस्ताव दे सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन और क्लाउड कम्प्यूटिंग में इन कदमों से भारत को तकनीकी नवाचार में ग्लोबल लीडर बनने में मदद मिलेगी।

रक्षा क्षेत्र, एयरोस्पेस और ई-कॉमर्स में एफ.डी.आई. की मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, इंटीलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन को मजबूत बनाने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए परसदीदा स्थान बन जाएगा, खासकर टैक्सनीली क्षेत्र में। कायदे-कानूनों का सरलीकरण करने और डिजिटल शासन से सरकार को बिजनेस वातावरण और बेहतर बनने की उम्मीद है और इससे एक पारदर्शी और प्रभावी इकोसिस्टम तैयार होगा, जिसमें नौकरशाही बाधाएं कम होंगी।